Indian J. Soc.& Pol. 04(02):2017:143-146 **ISSN 2348-0084(P)**
ISSN 2455-2127(O)

पं0 दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता

जितेन्द्र कुमार तिवारी[1]

[1]शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, आर बी एस कालेज आगरा, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

भारत प्राचीन काल से प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विरासत में अनेकता में एकत्व की दृष्टि वाला देश रहा है । प्राकृतिक संसाधनों की विविधता एवं पर्याप्तता के कारण अन्य राष्ट्र इस देश की ओर आकर्षित होते रहे हैं । वर्तमान आर्थिक एवं वैज्ञानिक विकास के दौर में भी इस राष्ट्र की मानवीय मेधा के उपयोग का आकर्षण आज भी बना हुआ है । राष्ट्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की उन्नति मानव मेधा के सदुपयोग पर निर्भर करती है । भारत की आवश्यकताओं के हिसाब से आर्थिक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी परम्परा व संस्कृति हमें बताती है कि मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं का पिण्ड नहीं वरन् वह एक आन्तरिक समन्वयकारी आध्यात्मिक तत्व से परिपूर्ण है, जो अपनी सम्पूर्ण शक्ति से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की समग्र सम्भावनाऐं रखता है। फिर भी वह उद्विग्न है, दिग्भ्रमित है, यथार्थ की भूमि से दूर है । इसके लिए आवश्यकता है दीनदयाल जी के आर्थिक विचारों के आधारभूत सत्य को स्वीकारने की जो वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिक है । उनका मानना था कि पश्चिम के प्रभाव के चलते हम अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं और पश्चिम का अंधानुकरण कर पिछड़ते जा रहे हैं । फलत: आर्थिक क्षेत्र ही नहीं वरन् जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समस्याएँ जन्म ले रही हैं। अत: भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुँचाने के लिए अपनी आवश्यकताएँ तय करके हर सम्भव उनकी प्राप्ति के अपनी ही सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक परिस्थितियों में प्रयास करने चाहिए तभी भारत के समग्र विकास का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है । इस दृष्टि से दृष्टव्य है– आर्थिक योजनाओं में वरीयता, कृषि उन्नयन, आर्थिक संसाधनों के उपयोग, उद्योगीकरण, व्यापार, संचार, ऊर्जा, उपभोग एवं आवश्यकताओं में संतुलन तथा प्रतियोगिता के दौर में मानवीय सहयोग आदि ।

***KEY WORDS:** दीन दयाल उपाध्याय,नियोजन,आर्थिक विकास,वैश्विक अर्थव्यवस्था*

आर्थिक योजनाओं एवं वरीयताओं की दृष्टि से

आर्थिक योजनाओं एवं वरीयताओं की दृष्टि से प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक विकास की योजनाएँ संवैधानिक नीतिनिर्देशक सिद्धान्तों के आधार पर बनाता है । हमारे देश में आर्थिक उन्नयन एवं विकास की योजनायें भी सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है । सरकारें राष्ट्र के उत्थान के लिए आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर नीति निर्धारण कर उनका क्रियान्वयन करती हैं । देश की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण सरकार की आर्थिक नीतियों पर निर्भर करता है । देश के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में आर्थिक आधारभूत तथा भारी उद्योगों में व्यापक पूँजी निवेश के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र के विकास की व्यवस्था की गई । लेकिन आज यह क्षेत्र निरन्तर कमजोर होता जा रहा है । जबकि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र विकास की प्राथमिकताओं को बल दिया जाता है। पं० दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन काल में बनी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगीकरण तथा रोजगार के विस्तार के लक्ष्य रखे गये तथा समाजवादी उद्देश्यों के अनुरूप सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में पूँजी विनियोजन की व्यवस्था की गई जिनमें कृषि की उपेक्षा कर औद्योगीकरण पर जोर देते हुए भारी उद्योगों को बल दिया गया, जो पं० दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार उचित नहीं था । अगर योजनाओं के लक्ष्यों और अनुमानों की गलतियों पर ध्यान दिया जाय तो भविष्य के विकास की दिशा को सुधारा जा सकता है ।

कृषि उन्नयन की दृष्टि से

1:Corresponding Author

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है क्योंकि देश की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है । देश के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का सर्वाधिक योगदान है । देश में कृषि विकास के लिए, कृषि की समस्याओं को दूर करने के लिए, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम नियोजित किये गये । दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास के लिए कुल व्यय का 17.7% व्यय का लक्ष्य रखा है जिनमें बड़ी योजनाओं के लिए खर्चे का प्रावधान अधिक है। जबकि दीनदयाल जी के विचारों को स्वीकार करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 1987 में किसानों का अधिकार पत्र नाम से एक प्रस्ताव अपनी राष्ट्रीय कार्य परिषद में स्वीकार किया था जिसमें किसानों के लिए न्यूनतम सुविधाएँ, न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के लक्ष्य के साथ पंचवर्षीय योजना में 75% राशि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए आवंटिक की गई थी । ये लक्ष्य पं० दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों के अनुरूप परिलक्षित होता है ।

वर्तमान सरकार के कुछ जन कल्याणकारी कृषि जागरुकता के कार्यक्रम निश्चित रूपेण सराहनीय है। भारतीय अनिश्चित कृषि के दुष्प्रभावों से कृषक की रक्षा के लिए कृषि आय बीमा योजना, कृषि उपकरणों के लिए कम ब्याज पर ऋण की सुविधा एवं नई कृषि तकनीक उर्वरक बीज, फसल, संरक्षण आदि की सामान्य कृषक को जानकारी के लिए संचार कार्यक्रम योजना सुखद एवं लाभकारी प्रतीत होते हैं किन्तु आम कृषक को कितना लाभ एवं ज्ञान मिल सकेगा, यह भविष्य के गर्त में समाया हुआ है । इस संदर्भ में उपाध्याय जी का मानना था कि हमें ज्ञान, विज्ञान सहयोग जहाँ से मिले, उन्हें प्राप्त कर लें और उसका उपयोग कर कृषि उत्पादन में विविधता एवं वृद्धि के प्रयास करें, तभी हमारा कल्याण होगा । उसके लिए हमारे देश की कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मानव जीवन एवं स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा ।

आर्थिक संसाधनों के उपयोग की दृष्टि से

प्रत्येक देश का आर्थिक विकास उस देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के उपयोग की क्षमता पर निर्भर करता है । भूमि, श्रम, पूँजी, प्रबन्ध और साहस उत्पादनों के साधनों का समुचित, व्यवस्थित एवं दीर्घकालीन योजना के अनुरूप उपयोग कर देश के आर्थिक विकास की दशा एवं दिशा को सुधारा जा सकता है। आर्थिक उत्पादन प्रकृति और मनुष्य के सम्मिलित प्रयत्नों से ही होता है । प्राकृतिक संसाधनों का विधान हम इस प्रकार कर लें कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाये, ये देश के नागरिकों की कुशलता पर निर्भर करता है। अपने देश में उपलब्ध मानव संसाधन का अधिकतम सुव्यवस्थित उपयोग हेतु भारतीय जीवन पद्धति एवं मानव के स्वाभिमान को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है ।

औद्योगीकरण की दृष्टि से

आज आर्थिक विकास की रीढ़ उद्योग बन चुका है । देश का औद्योगिक विकास आर्थिक परिस्थितियों एवं औद्योगिक नीतियों पर निर्भर करता है । अगर देश में उपलब्ध संसाधनों, जन साधारण की आवश्यकताओं, पूँजी निवेश, श्रम उपयोगिता, क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास हेतु औद्योगिक नीति निर्धारित की जाती है, तभी देश का संतुलित विकास सम्भव है । विश्व विकास के बढ़ते कदमों के साथ तालमेल करते हुए विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन बुरा नहीं है किन्तु मिश्रित अर्थव्यवस्था के देश में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों को संतुलित महत्व प्रदान करने तथा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों को वरीयता देने, बड़े एवं छोटे उद्योगों में सामन्जस्य, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देने, उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखने से ही औद्योगिक विकास सम्भव है । इस दृष्टि से उपाध्याय जी की समन्वयकारी आर्थिक दृष्टि आज भी प्रासंगिक है ।

व्यापार की दृष्टि से

देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए घरेलू व्यापार एवं विदेशी व्यापार महत्वपूर्ण है । देश के विदेशी व्यापार पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होता है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हमारे आयात व्यय में हिस्सा कम हुआ है । यूरोप, एशिया, अफ्रीका आदि देशों का भारत के निर्यात आय में हिस्सा कम हुआ है । मात्र तेल निर्यातक देशों का निर्यात बढ़ा है । भारत के परम्परागत निर्यातों की माँग की लोच बहुत कम है । देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से आयात-निर्यात में संतुलन होना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं हुआ । व्यापारिक स्थितियाँ बताती हैं कि हमारे देश में विगत दशक में आयात बढ़ा है और निर्यात कम हुआ है । हमारे देश में विदेशी व्यापार की तुलना में अन्तर देशीय व्यापार अधिक है । आर्थिक क्षेत्र में व्यापार की ओर अग्रसर होने के लिए स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य शासन को व्यापार में भाग लेना

था । उपाध्याय जी का मानना था कि सैद्धान्तिक दृष्टि से शासन द्वारा व्यापार का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए । हमारे यहाँ तो कहा गया है कि शासन को व्यापार तथा व्यापार को शासन नहीं करना चाहिए । इस दृष्टि से उपाध्याय जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं।

संचार की दृष्टि से

संचार आज एक प्रमुख आधारभूत संरचना है । संचार के विकास पर देश का औद्योगिक, व्यापारिक एवं आर्थिक विकास निर्भर करता है । इसके अन्तर्गत डाक सेवा, दूर संचार, कम्प्यूटर, इंटरनेट के सर्वतोन्मुखी उपयोग नें क्रान्ति ला दी है । भारतीय डाक नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है । बिना संचार के हम किसी भी प्राकर के औद्योगिक व्यापारिक विकास को नहीं कर सकते । वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल के लिए संचार अपरिहार्य अंग है जिसके परिणामस्वरूप एक देश की आर्थिक घटना दूसरे देश पर प्रभाव डालती है । तत्कालीन सरकार ने 1999 में दूरसंचार नीति की घोषणा की और देश में टेलीफोन उपलब्धि को 2010 तक 15 प्रति हजार लाने का लक्ष्य है । इस नीति के फलस्वरूप B.S.N.L. के एकाधिकार को समाप्त कर निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया । जिसने प्रतियोगिता को जन्म देकर सस्ती संचार सेवाएँ उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किए । आर्थिक विकास की दृष्टि से यह एक सराहनीय कदम है जिससे देश का प्रत्येक व्यक्ति देश की समस्त परिस्थितियों से परिचय प्राप्त कर जागरुक होगा । उपाध्याय जी की यही धारणा थी कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक समस्त परिस्थितियों से परिचय प्राप्त कर जागरुक बने ।

ऊर्जा की दृष्टि से

स्वतंत्रता के बाद आधारिक संरचना के क्षेत्र में संचार, परिवहन, ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ है । समस्त आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा की भूमिका बढ़ती जा रही है । अत: देश के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह ऊर्जा के उत्पादन, वितरण एवं उपयोग के कल्याणकारी नीतिगत निर्णय ले, वही अपने देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के दूरगामी उपयोग की योजना बनाये और जल ऊर्जा, तापीय ऊर्जा एवं परमाणु ऊर्जा का आर्थिक विकास के लिए ठीक प्राकर से उपयोग करे । आज देश में ऊर्जा उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है । किन्तु फिर भी बढ़ती जनसंख्या एवं उपकरणों हेतु पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध नहीं है । सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास के लिए बिजली अधिनियम 2003 बनाया जिसमें सम्पूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण पर जोर, बिजली वितरण प्रबन्धन में सुधार की दृष्टि से गैर सरकारी संगठनों का प्रयोग, निजी क्षेत्र का प्रावधान, बिजली चोरी रोकने सम्बन्धी प्रावधान किये जिनका उद्देश्य अधिकतम लोगों को बिजली की सुविधाएँ उपलब्ध कराना है । उपाध्याय जी का ये विचार कि सरकार की योजनाओं का सभी व्यक्तियों को अधिकतम लाभ मिले, तभी समग्र राष्ट्र का कल्याण सम्भव है । आज भी प्रासंगिक है ।

उपभोग एवं आवश्यकताओं में संतुलन की दृष्टि से

देश के आर्थिक विकास में उत्पादन एवं उपभोग के संतुलन की आवश्यकता होती है । अगर वस्तु का उत्पादन कम होता है और उपभोग की स्थितियाँ ज्यादा हों, तो वस्तु की मूल्य वृद्धि होती है । जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है । मानवीय आवश्यकताएँ अनन्त है, साधन सीमित है । साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज ने अगर आवश्यकताओं को नियंत्रित नहीं किया या उत्पादन के साथ तालमेल नहीं बैठाया तो राष्ट्र का आर्थिक विकास अवरुद्ध तो होगा ही साथ ही नयी पीढ़ी के लिए समस्याएँ भी उत्पन्न होंगी । वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को बहुत अधिक बढ़ा लिया है और वह भोग और अर्थ की लालसा में समस्याओं के चक्रव्यूह में फँसा है । उपाध्याय जी का मानना था कि देश के आर्थिक विकास के लिए उत्पादक वस्तुऐं उतनी ही हों जितनी नितांत आवश्यक हों । इससे श्रम और शक्ति के शोषण का बचाव सम्भव है । इसके लिए लम्बी प्रक्रिया का त्याग तथा उत्पादन, उपभोग एवं आवश्यकताओं में संतुलन की आवश्यकता है । भारतीय संस्कृति के जीवन के सिद्धान्त, आवश्यकता से अधिक संचय न करने, के सिद्धान्त के अनुसरण के समग्र राष्ट्र के आर्थिक विकास और कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा । यह विचार आज की परिस्थितियों में भी प्रासंगिक है ।

प्रतियोगिता के दौर में मानवीय सहयोग की दृष्टि से

वर्तमान युग प्रतियोगिता का युग है जिससे आर्थिक क्षेत्र भी अछूता नहीं है । देश के आर्थिक क्षेत्र में सर्वत्र

प्रतियोगिता दिखाई देती है । पूँजीपति, उद्योगपति, श्रमिक, व्यापार आदि के विकास लालसा ने शोषण को जन्म दिया है । प्रगति की लालसा ने मानवीय सहयोग का भाव क्षीण कर दिया है । देश के कल्याण के लिए मानवीय सहयोग का भाव अपरिहार्य तथ्य है । मानवतावादी विचारों के पोषक पं० दीनदयाल उपाध्याय ने जन कल्याण के लिए मानवीय सहयोग को महत्वपूर्ण माना है । आज उद्योग के क्षेत्र में उद्योगपति सरकारी नीतियों का दुरुपयोग कर अपने आर्थिक लाभ के लिए जन कल्याण को त्याग देते हैं। उपभोग की वस्तुओं से अधिकतम लाभ के लिए उसकी गुणवत्ता को भी मानकों के अनुरूप नहीं रखते । चाहे उसका प्रभाव उपभोगकर्ता के जीवन पर नकारात्मक क्यों न पड़े । व्यापारी के लिए लाभ ही लक्ष्य है। चाहे वह समाज के पतन की कीमत पर ही क्यों न हो । मानव कल्याण की कीमत पर कोई लाभ नहीं चाहिए । आज राष्ट्र में मानवीय सहयोग आवश्यक है ।

सन्दर्भ :

उपाध्याय, पं० दीनदयाल (1994) *भारत की अर्थनीति : विकास की दिशा,* लखनऊ,लोकहित प्रकाशन,

----------(1986) *एकात्मक मानववाद,* नोएडा, जागृति प्रकाशन,

----------(1979) *राष्ट्र जीवन की दिशा,* लखनऊ,लोकहित प्रकाशन.

कपिल, एच. के.,(2001) *अनुसन्धान विधियाँ,* , आगरा विनोद प्रकाशन मन्दिर,

कुलकर्णी, शरद अनन्त (1987) *एकात्म अर्थनीति,* सुरुचि प्रकाशन,

शर्मा, महेश चन्द्र, दीनदयाल उपाध्याय (1994) *: कृतित्व एवं विचार,* नई दिल्ली, वसुधा पब्लिकेशन्स,